विभागीय आधार पर चलाये जाने वाले उन प्रतिष्ठानों जिनमें 500 अथवा अधिक कर्मकार नियोजित हैं, पर अनुप्रयोज्य बनाया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्यिक तथा सेवा संगठनों में, जिनका बड़े पैमाने पर जनता के साथ संबंध है, बेहतर ग्राहक सेवायें प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1977 में कर्मकारों की भागीदारी की एक और योजना आरम्भ की थी। इन योजनाओं के कार्य की समीक्षा की गयी थी और भारत सरकार ने 30 दिसम्बर, 1983 को प्रबन्धन में कर्मकारों की भागेदारी योजना अधिसूचित की थी। यह योजना विशेष रूप से छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों को छोड़कर सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर लागू है। इस योजना में शाप फ्लोर तथा प्लान्ट स्तर पर कर्मकारों की सहभागिता की व्यवस्था है। जहां तक बोर्ड स्तर पर सहभागिता का प्रश्न है संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, श्रम मंत्रालय के साथ विचार विमर्श करके निर्णय ले सकते हैं। चल रहे 214 सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से 104 ने शाप/प्लान्ट स्तर मंचों का गठन किया है। अन्य 62 उद्यमों ने योजना को संशोधित रूप में लागू किया है। भागीदारी व्यवस्था में परिचालात्मक क्षेत्र, आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र, कार्मिक मामले, कल्याण क्षेत्र, उत्पादन, पर्यावरणीय तथा सामुदायिक विकास शामिल है। प्रबन्ध में कर्मकारों की सहभागिता विधेयक, 1990, जिसे राजभाषा में पेश किया गया था, संसद् के विचार विमर्श के लिये लम्बित है।

Pension scheme for workers of provident fund organisation

*379. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether the Employees' Provident Fund Organisation has worked out a separate Pension Scheme for its subscribers; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) and (b) The Central Board of Trustees, Employees' Provident Fund had recommended introduction of a Pension Scheme for the EPF Subscribers. The Central Government considered the recommendations of the Board and has since decided to introduce a Pension Scheme for the EPF subscribers with effect from 1.4.1993. The Scheme provides for payment of monthly pension in the contingencies of death, permanent total disablement, supperannuation, retirement etc. The amount of monthly pension will depend upon the pensionable service and pensionable salary of the member. Minimum 10 years membership of the fund will be rqeuired for entitlement to pension.

As regards the workers of the Employees' Provident Fund Organisation, they are already entitled to pension as admissible to the employees of Central Government.

Action against ITDC Under provident Fund Act

*380. SHRI V. GOPALSAMY:
SHRI MISA R. GANESAN:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the number of 7A and 14B proceedings under the Employees Provident Fund & Miscellaneous provision Act, 1952 initiated against the ITDC management by PF authorities during the last three years, yearwise;

(b) the number of cases where PF authorities passed orders against ITDC management, yearwise;

(c) the number of cases where ITDC management filed appeals or writ petitions against orders of the PF authorities;